

## दिवालिया कानून को मजबूत करना

सामान्य अध्ययन – पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों का नियोजन, गतिशीलता, विकास, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

कीवर्ड : इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एडजुडिकेटर्स, कमर्शियल बैंक, लेनदार, रेज़ोल्यूशन, रियल-एस्टेट इनसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट देनदार, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी।

संदर्भ :

- दिवालिया कानून की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए , सरकार ने कई बदलावों का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करना, प्री-पैकेज्ड ढांचे के दायरे का विस्तार करना और न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विकसित करना शामिल है।



मुख्य प्रस्ताव:

- आईबीसी के कामकाज को मजबूत करने के लिए कोड में बदलाव के संबंध में विचार किया जा रहा है
  - कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) अनुप्रयोगों का प्रवेश।
  - दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
  - शोधन प्रक्रिया को पुनर्गठित करना।
  - संहिता के तहत सेवा प्रदाताओं की भूमिका।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव दिया है जो कोड के तहत न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ कई प्रक्रियाओं को संभाल सके।
- मंत्रालय ने फास्ट-ट्रैक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (एफआईआरपी) को फिर से डिजाइन करने का भी प्रस्ताव दिया है।

- यह वित्तीय लेनदारों को अंतिम परिणाम की कानूनी निश्चितता में सुधार करने के लिए सहायक प्राधिकरण (एए) की कुछ भागीदारी को बनाए रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया के बाहर कॉर्पोरेट देनदारों (सीडी) के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया को चलाने की अनुमति देता है।
- रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए समाधान प्रक्रिया के संबंध में कुछ बदलाव भी प्रस्तावित किए गए हैं।
  - उदाहरण के लिए, समाधान पेशेवर को सीओसी (कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स) की सहमति से भूखंड, अपार्टमेंट या भवन का स्वामित्व और कब्जा आवंटियों को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाना।

#### आईबीसी क्या है?

- **इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) 2016** को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। इसे मई 2016 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।
- दिवालियापन को हल करने के लिए दिवालियापन कोड एकमात्र समाधान है, जो पहले एक लंबी प्रक्रिया थी जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यवस्था की पेशकश नहीं करती थी। कोड का उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को कम बोझिल बनाना अर्थात् ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है।
- दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। जब चुकौती में चूक होती है, तो लेनदार देनदार की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और दिवालियापन को हल करने के लिए निर्णय लेने चाहिए। आईबीसी के तहत देनदार और लेनदार दोनों एक दूसरे के खिलाफ 'वसूली' की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
- कंपनियों को आईबीसी के तहत 180 दिनों के भीतर दिवालियापन की पूरी कवायद पूरी करनी है। यदि लेनदारों ने विस्तार पर आपत्ति नहीं जताई तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 1 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली स्टार्टअप सहित छोटी कंपनियों के लिए दिवालियापन की पूरी कवायद 90 दिनों में पूरी की जानी चाहिए और समय सीमा 45 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। यदि ऋण समाधान नहीं होता है तो कंपनी के लिए शोधन जाती है।

#### प्रस्तावों की कमियां:

लेकिन प्रस्ताव सभी पक्षों द्वारा रचनात्मक व्याख्या के लिए व्यापक अंतराल छोड़ते हैं।

- उदाहरण के लिए, यह प्रस्ताव कि न्यायनिर्णायकों के पास उन लोगों को दंडित करने का अधिकार होना चाहिए जो पीठ के समक्ष "निन्म (फ्रिवुल्स) " आवेदन दायर करते हैं, यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि किसे तुच्छ माना जाएगा।
- यह न्यायनिर्णायकों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करेगा, और इसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हो सकती है।
- फास्ट-ट्रैक कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस को फिर से डिजाइन करने का सुझाव एक फिसलन भरी ढलान की तरह दिखता है जिसे आवेदकों के एक समूह को दूसरे के पक्ष में करने के लिए मोड़ा जा सकता है।
- एक और दोष आईबीसी प्रस्तावों में परिचालन लेनदारों, विशेष रूप से व्यक्तियों की कानूनी एजेंसी को कम करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को पुनर्गठित करने का प्रयास करने के तरीके में निहित है।
  - यह अचल संपत्ति दिवालियापन को हल करने के सुझाव में दिखाई देती है; एक अन्य संघर्षरत परियोजना में परिवारों द्वारा शुरू की गई समाधान प्रक्रिया से एक रियल एस्टेट कंपनी की चल रही परियोजनाओं को प्रतिबंधित करने का तर्क क्षेत्र के प्रति एक संस्थागत पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

- एक बिल्डर के लिए एक विशिष्ट रियल एस्टेट परियोजना के लिए दिवालियेपन का दावा करने की अनुमति दी जाना अजीब है, लेकिन कानूनी रूप से अन्य परियोजनाओं के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

- इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का सुझाव है कि परिचालन लेनदारों को समाधान के लिए दाखिल करने से पहले संस्थानों से चूककर्ता पक्ष के बारे में सभी जानकारी एकत्र करनी चाहिए (जो एक कठिन कार्य हो सकता है), गलत करने वाले के बजाय गलत पार्टी पर बोझ डालते हुए।
- खाली बेंचों या बेहतर-योग्य अधिकारियों के मुद्दे को सीधे संबोधित किए बिना, यह समाधान प्रक्रिया की दक्षता और गति में सुधार करने का प्रयास नाकाफी मालूम होता है।

**निष्कर्ष:**

- फास्ट-ट्रैक सीआईआरपी को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रखने से सीआईआरपी के त्वरित निपटान में सहायता मिल सकती है।
- हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि आईबीसी में प्रदान किए गए ढांचे के भीतर वित्तीय लेनदारों के अलावा अन्य हितधारकों के हितों को संरक्षित किया जायेगा।
- दिवालियेपन के मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों पर भरोसा करने के बजाय सिस्टम की मानव क्षमता की कमी को दूर करने की आवश्यकता होगी, ताकि प्रशासकों के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त हो सके।

**प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:**

प्र. इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. आईबीसी 2016 भारत का दिवालियापन कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट लेनदारों को संकट से निकालना है।
2. संहिता किसी भी मुकदमे सहित एक समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है, जिसे 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से असत्य है/हैं ?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों।
- d) न तो 1 और न ही 2।

उत्तर: (a)

### व्याख्या

- आईबीसी 2016 भारत का दिवालियापन कानून है; यह दिवालियापन और दिवालियापन के लिए एकल कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को मजबूत करना चाहता है। कुछ साल पहले तक, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अदालतों के अधीक्षण के तहत कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को विनियमित किया गया था – जो एक कुशल प्रक्रिया नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप अनुचित देरी होती थी।
- आईबीसी के प्रवर्तन के साथ, समापन प्रक्रिया अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की देखरेख में है, जो एक फर्म द्वारा ऋण चूक के प्रारंभिक चरण के दौरान त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक इष्टतम वसूली दर तय होती है।
- आईबीसी का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदारों को संकट से निकालना है। (इसलिए विकल्प 1 गलत है)।
- संहिता किसी भी मुकदमे सहित एक समयबद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है, जिसे 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए विकल्प 2 सही है।
- निस्संदेह, आईबीसी अब तक काफी हद तक प्रभावी रहा है; हालाँकि, समयसीमा का अनुपालन एक मुद्दा बना हुआ है। मुद्दों को हल करने के लिए 180 दिनों (+90 दिनों का विस्तार) की पूर्व परिकल्पित समय सीमा को बढ़ाकर 330 दिन कर दिया गया था। विस्तार के बावजूद, संकल्प योजनाएँ समय सीमा के अंदर पूरी नहीं हो सकी।

चूंकि केवल कथन 1 गलत है, इसलिए सही विकल्प (a) केवल 1 है।

### मुख्य परीक्षा प्रश्न:

**Q.** आईबीसी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है जिसे अगर प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता है तो यह कॉर्पोरेट क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लिए बड़े लाभ पैदा कर सकता है। कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

### स्रोत: मिनट

